© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 05 , Issue : 03 | January – March 2018

काम का अधिकार: भारत में मौलिक अधिकार के रूप में कार्य करने का अधिकार : एक विवेचना

शिव प्रताप यादव , शोधछात्र , राजनीति एवं लोकप्रशासन विभाग
डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ (उ०प्र०)

सार : मानवाधिकार की स्थापना 2 अक्टूबर 1993 में हुई। जिसके उद्देश्य नौकरशाही पर रोक लगाना, मानव अधिकारों के हनन को रोकना तथा लोक सेवक द्वारा उनका शोषण करने में अंकुश लगाना। मानवाधिकार की सुरक्षा के बिना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी खोखली है मानवाधिकार की लड़ाई हम सभी की लड़ाई है। विश्वभर में नस्ल, धर्म, जाति के नाम मानव द्वारा मानव का शोषण हो रहा है। अत्याचार एवम जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात् धर्म एवम जाति के नाम पर भारतवासियों को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। आदमी गौर हो या काला, हिन्दू हो या मुस्लमान, सिख हो या ईसाई, हिंदी बोले या कोई अन्य भाषा सभी केवल इंसान हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानवाधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है। मानव अधिकार का मतलब ऐसे हक़ जो हमारे जीवन और मान-सम्मान से जुड़े हैं।

19वीं शताब्दी की शुरुआत में सामाजिक उथल-पुथल के प्रकाश में फ्रांसीसी समाजवादी नेता लुई ब्लैंक ने वाक्यांश "187 के वित्तीय संकट के चलते बेरोजगारी बढ़ाई और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया। संपत्ति का अधिकार राजनीतिक आजादी और समानता, और संपत्ति के सामंती नियंत्रण के खिलाफ शुरुआती खोजों में एक महत्वपूर्ण मांग थी। संपत्ति उन अधिकारों के आधार के रूप में कार्य कर सकती है जो जीवन स्तर के पर्याप्त मानक के अधिकार की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं और यह केवल संपत्ति मालिक थे जिन्हें प्रारंभ में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट देने का अधिकार दिया गया था।

क्योंकि हर कोई एक संपत्ति मालिक नहीं है, काम करने का अधिकार सभी को जीवन स्तर के पर्याप्त मानक प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए स्थापित किया गया था। आज संपत्ति स्वामित्व के आधार पर भेदभाव को मानवाधिकारों के समान आनंद के लिए गंभीर खतरा माना जाता है और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार

उपकरणों में गैर-भेदभाव खंडों में अक्सर संपत्ति को आधार के रूप में शामिल किया जाता है जिसके आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, राज्यों द्वारा पारित "काम करने का अधिकार" कानून कभी-कभी यूनियन आयोजन को कम करने का प्रयास करता है। अन्य मामलों में, उन्हें पेशेवर संगठनों द्वारा शासित पेशेवर क्षेत्रों समेत कुछ पदों के लिए योग्यता के विनियमन के खिलाफ निर्देशित किया गया है। कई अमेरिकी राज्यों ने कानून तैयार करने, परीक्षण करने, या शैक्षणिक आवश्यकताओं की आवश्यकता वाले कानूनों को पारित किया है, अक्सर बीमार लोगों के बारे में मतदाता शिकायतों के जवाब में, जैसे कि चिकित्सा विशेषज्ञता का दावा करने वाले लोग। फ्राइडमैन ने 1980 में बताया कि आज आप एक वकील, एक चिकित्सक, एक दंत चिकित्सक, प्लंबर, एक नाई, एक चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं या किसी अन्य अधिकारी में संलग्न नहीं हैं, बिना किसी सरकारी अधिकारी से परमिट या लाइसेंस प्राप्त किए बिना।

क्षमता के स्तर को सुनिश्चित करने के प्रयास में मौजूदा कानूनों और उनके संगठनों द्वारा कई कानूनों का समर्थन किया गया था। अन्य पर्यवेक्षकों का मानना है कि उनके प्रयासों को शुल्क के लिए कीमतों में वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा को रोकने पर निर्देशित किया गया था। जवाब में, उद्यमियों और कार्यकर्ताओं ने एक जीवित कमाई के अधिकार के लिए संवैधानिक सुरक्षा को सुरक्षित करने वाले कई अदालतों के मामलों को जीता है। ऐसे मामलों ने लुइसियाना भिक्षुओं के लिए काम करने का अधिकार जीता है जो कैस्केट बेचते हैं, फिलाडेल्फिया स्वतंत्र टूर गाइड, कोलोराडो टैक्सी ड्राइवर, और कनेक्टिकट इंटीरियर डिजाइनर।

काम करने का मानव अधिकार(The human right to work)

काम करने का मानव अधिकार काम को पहचानता है जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति हकदार होता है। सबसे पहले, मानव समाज के उत्पादन और सेवा गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार और इन संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से अर्जित लाभों में भाग लेने का अधिकार जो कि पर्याप्त स्तर पर रहने की गारंटी देता है। इस प्रकार काम करने का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक क्षेत्र से कोई भी बाहर नहीं रखा गया हो।

एक व्यक्ति जो काम करता है वह संसाधनों, शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच पर निर्भर करता है। मजदूरी-नियोजित व्यक्ति या स्व-नियोजित व्यक्ति के रूप में कार्य का आनंद लिया जा सकता है। काम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह व्यक्तियों को अपनी जिंदगी कमाने की अनुमति देता है।

काम करने का अधिकार है कि संसाधनों के लिए काम और पहुंच इस तरह वितरित की जाती है जो काम करने के इच्छुक हर किसी की भागीदारी के लिए कम हो जाती है। किसी के जीवन को कमाने का अधिकार, कम से कम, इन आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ पर्याप्त जीवन स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

काम करने का अधिकार किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में भागीदारी से संतुष्ट नहीं है। असल में, इसमें "हर किसी का अधिकार उस काम से अपना जीवन जीने का अवसर शामिल है जिसे वह स्वतंत्र रूप से चुनता है या स्वीकार करता है।" किसी के जीवन को कमाने के लिए आर्थिक गतिविधि में पसंद और आजादी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए काम करने का अधिकार न केवल उस काम को वितरित किया जाता है जो हर किसी की भागीदारी के लिए अनुमति देता है, बल्कि यह भी कि किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी कमाने के तरीके में प्राथमिकता मानव अधिकार गारंटी भी है। किसी के जीवन को कमाने के अधिकार के अलावा, लेख 6 इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने गए या स्वीकार्य काम का मानव अधिकार स्थापित करता है। यहां "स्वीकृत कार्य" शब्द का अर्थ मजदूरी के रोजगार को दर्शाता है जबकि "चुने हुए काम" को स्व-रोज़गार के रूप में देखा जा सकता है।

क्या यह सही है कि आप जो भी महसूस करते हैं, वह कर सकते हैं, इसे कॉल करें और इसके लिए राज्य वेतन मांगें? स्वतंत्र रूप से चुने गए या स्वीकृत काम का अधिकार यूटोपियन प्रतीत हो सकता है। हालांकि, एक करीबी रूप से पता चलता है कि यह अधिकार वास्तव में काफी उचित है।

इसका मतलब यह नहीं है कि, उदाहरण के लिए, हर कोई जो पूर्णकालिक संगीतकार बनना चाहता है उसे अपने जीवन को इस तरह से कमाने का अधिकार है। स्वतंत्र रूप से चुने गए या स्वीकार्य काम का अधिकार सशर्त है, ज़ाहिर है, इस नौकरी के साथ किसी के जीवन की कमाई की संभावना पर। इसलिए, पूर्णकालिक संगीतकार होने पर केवल काम माना जा सकता है यदि इसे इस तरह से पुरस्कृत किया जाता है कि कोई व्यक्ति इसके साथ रह सकता है।

काम करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरणों (जैसे आईएलओ कन्वेंशन एनआर 159) में मान्यता प्राप्त है, जो अन्य मानवाधिकारों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है और मानव गरिमा के एक अविभाज्य और निहित हिस्से को बनाता है।

साथ ही यह व्यक्ति और उसके परिवार को एक जीवित कमाई करने की अनुमति भी देता है। काम के रूप में स्वतंत्र रूप से चुने या स्वीकार किए जाते हैं, यह समुदाय के भीतर व्यक्तिगत विकास और मान्यता को बढ़ावा देता है।

काम करने का अधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों (आईसीईएससीआर) के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अनुच्छेद 6, 7 और 8 द्वारा पूरी तरह से विस्तारित किया गया है जो क्रमशः एक जीवित, निष्पक्ष और अनुकूल स्थितियों का अधिकार और अधिकार प्राप्त करने के अधिकार के साथ सौदा करता है। सभी मनुष्यों के लिए ट्रेड यूनियन बनाने के लिए।

रोजगार समानता निर्देश (Employment Equality Directive)

2000 में अपनाए गए रोजगार समानता निर्देश रोजगार और व्यवसाय, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नियोक्ता या कर्मचारी संगठनों की सदस्यता के क्षेत्र में धर्म और विश्वास, आयु, अक्षमता और यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

निर्देश के अनुच्छेद 5 में यह बताया गया है कि नियोक्ता को अक्षमता वाले व्यक्ति को रोज़गार में भाग लेने, भाग लेने या अग्रिम करने के लिए उचित प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है, जब तक कि ऐसे उपायों नियोक्ता पर असमान बोझ नहीं लगाएंगे ।

भारत में मौलिक अधिकार के रूप में कार्य करने का अधिकार

काम करने का अधिकार है कि लोगों को उत्पादक रोजगार में काम करने या संलग्न करने का मानव अधिकार है और ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता है। काम करने का अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) में स्थापित है और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में शामिल होने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में मान्यता प्राप्त है, जहां काम करने का

अधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर जोर देता है । संविधान के प्रस्ताव भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करते हैं। डीपीएसपी में एक ही संकल्प को और अधिक व्यापक रूप से दोहराया जाता है, जिसमें दूसरों के बीच विशेष रूप से राज्य की आय में असमानताओं को कम करने और स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने के साथ-साथ अपनी नीति को निर्देशित करने के लिए "स्वामित्व और नियंत्रण" समुदाय के भौतिक संसाधनों को सामान्य अच्छे उप-सेवा के लिए सबसे अच्छा वितरित किया जाता है "और यह कि आर्थिक व्यवस्था के संचालन के परिणामस्वरूप आम हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता नहीं होती है। एक समय में, एफआरएस को डीपीएसपी पर प्राथमिकता थी। लेकिन हाल के दिनों में, कुछ डीपीएसपी भाग III के तहत नामित एफआर का एक अभिन्न अंग बन गया है और बन गया है। इसलिए, डीपीएसपी के प्रवर्तन के लिए राज्य या न्यायपालिका की मंजूरी की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. कश्यप सुभाष : (1978) Human Rights and the Parliament (New Delhi: Metropolitan Company).
2. शास्त्री , TSN (2005) India and Human Rights (Delhi: Publishing House Company).
3. सक्सेना के पी (1999) (ed.) Human Right and the Constitution: Vision and Reality (New Delhi: